

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10  
/ 25

पत्रावली पेश हुई वकील उस कार उपस्थित  
पत्रावली में कोई कोने की वजह से प्रकरण  
में सुमार्ज नहीं हो सकी अतः पत्रावली  
दिनांक 10-11-25 को पेश हो

संख्या :

10 म  
/ 25

पत्रावली पेश ही वकील पत्रकार उपो। मिश्र  
में वादी एवम् प्रतिवादी गण ने उपो को  
निवेदन किया कि व्यापार का काग के अन्त  
प्रकरण में अत एव प्रकरण के प्रथम राजीनामा  
हो गया है अतः उक्त वाद में अत कोई  
कार्य वादी नहीं चाहते है वादी की पक्षजन  
वादी आदि द्वारा एवम् प्रतिवादी गण की पक्षजन  
प्रतिवादी आदि द्वारा करायी गयी। पत्रकार  
के निवेदन को व्यापार में स्वीकार किया  
गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के वा राजीनामा  
के आधार पर खरीज किया जाता है पत्रावली  
दिनांक शुक्र होकर वाकील एवम् हो।

निवेदन आज दिनांक 10-11-2025 को कर  
करवाया गया।

Handwritten marks and signatures on the right margin.

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

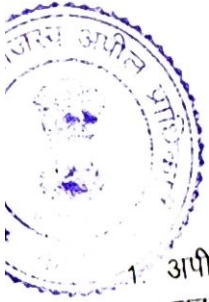
ल संख्या : 15/329

- K.K.V. - 1 सतीश चन्द आत्मज श्री सूरजमल जी आयु 43 वर्ष ।  
 मजिस्ट्रेट - 2 शशिकान्त पुत्र सूरजमल आयु 44 वर्ष जाति अहीर निवासीगण ग्राम बडौद तहसील  
 दीगोद जिला कोटा । ---अपीलान्ट

### बनाम

- म अर्जी - 1. अरुण कुमार पुत्र श्री सूरजमल आयु 50 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम बडौद तहसील  
 लाडपुरा जिला कोटा ।  
 2. हरिशचन्द्र पुत्र श्री सूरजमल आयु 46 वर्ष जाति अहीर बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा  
 3. सूरजमल आत्मज देवीलाल उम्र 80 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद  
 जिला कोटा ।  
 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा । ---रेस्पोंडेंट

- उपरिष्ठत :- 1. श्री गोविन्द सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।  
 2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोंडेन्ट की ओर से ।



### निर्णय

दिनांक: 04.08.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा लोक अदालत कैम्प कोटडादीप सिंह द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र वास्ते ग्राम बडौद में खाता संख्या 584 में हिस्सा दर्ज कराने बाबत पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि पक्षकारान की शामलाती खातेदारी की भूमि है जिसमें सूरजमल पुत्र देवीलाल व सतीशचन्द्र, हरिशचन्द्र, शशिकान्त आत्मज श्री सूरजमल जाति अहीर बहिस्सा बांट बराबर के दर्ज है । प्रार्थी का हिस्सा 1/2 व सतीशचन्द्र, हरिशचन्द्र, शशिकान्त आत्मज सूरजमल हिस्सा 1/2 दर्ज करवाना चाहता है और उसी अनुसार काबिज काश्त है ।

सत्य प्रतिलिपि

अपील प्राधिकारी

13

न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 के द्वारा वादी अरुण कुमार पुत्र को ग्राम बडौद की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 662 रकबा 6.78 हैक्टर भूमि में कम 1 से 4 के साथ बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित किये जाने का निर्णय एवं पारित की।

नरथ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 से व्यथित कर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने व अधीनरथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनरथ न्यायालय में बिना अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट कम 02 को सूचना दिये ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनरथ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें सूरजमल का 1/2 हिस्सा, सतीशचन्द्र, हरिशचन्द्र, शशिकान्त का 1/2 हिस्सा दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधीनरथ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। शिविर में जो प्रार्थना पत्र पेश हुआ है उसमें भी सूरजमल का 1/2 हिस्सा दर्शाया गया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार सूरजमल का केवल 1/4 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी में अरुण कुमार का कोई हिस्सा नहीं है। राजस्व लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निरतारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर ही निर्णय किये जाते हैं परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनरथ न्यायालय ने पक्षकारान को सूचना दिये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है उक्त निर्णय बिना प्राथमिक डिक्री पारित किये ही सीधे अंतिम डिक्री कर दिया गया है जो निरस्तनीय है। अधीनरथ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र सूरजमल के द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट कम 2 हरिशचन्द्र के नाम से पेश हुआ है उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे ना ही वह कैम्प में मौजूद थे। इस प्रकार अधीनरथ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनरथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 निरस्त फरमाया जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि बन्दोबस्त विभाग ने वादग्रस्त आराजी में सूरजमल के तीन वारिसान का नाम दर्ज कर दिया और अरुण का नाम दर्ज नहीं किया जिसे अधीनरथ न्यायालय ने दर्ज किया है। प्रस्तुत प्रकरण में सूरजमल ने कैम्प कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सम्पत्ति में बराबर-बराबर का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है इसी आधार पर अधीनरथ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनरथ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जावे।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मन्ग किया। बन्दोबस्त विभाग ने वादग्रस्त आराजी में सूरजमल के तीन वारिसान का नाम दर्ज कर दिया और अरुण का नाम दर्ज नहीं किया जिसे अधीनरथ न्यायालय ने दर्ज किया है। प्रस्तुत प्रकरण में सूरजमल ने कैम्प कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें सम्पत्ति में बराबर-बराबर का नाम दर्ज करने का निवेदन किया है इसी आधार पर अधीनरथ न्यायालय ने

सत्य प्रतिलिपि

10/06/2015

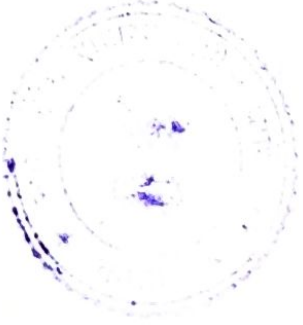
10/06/2015

डिक्री पारित की है। ग्राम पंचायत बडौद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर गैर कानूनी एवं डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं। हग अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2015 बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज कुमार ओझा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



राजस्व अपील प्राधिकारी  
कोटा